



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587 ]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922

No. 587]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 880(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय सिविल लेखा सेवा भर्ती (समूह क) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह क) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह क) भर्ती नियम, 1977 में,—  
(क) नियम 3 में, उपनियम (3) के खंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :—  
“(vii) महालेखा नियंत्रक—26000 रु. (नियत)”;  
(ख) अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के सामने श्रेणी शीर्षक के नीचे, “महालेखा नियंत्रक—24050-650-26000 रु.” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—  
“महालेखा नियंत्रक—26000 रु. (नियत)”।

[सं. ए-12018/2/96/एम एफ सी जी ए/श्रेणी क]

वी. एन. कैला, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं सा.का.नि. 537 तारीख 14 अप्रैल, 1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किए गए,—

- (i) सा. का. नि. 125 तारीख 27 जनवरी, 1989,
- (ii) सा. का. नि. 434(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1992 और
- (iii) सा. का. नि. 12(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 1999,

**स्पष्टीकारक ज्ञापन**

केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (कार्यान्वयन सेल) का. ज्ञा. सं. 6/1/1998 आई.सी.आई. तारीख 30-6-1999 द्वारा संगठित समूह 'क' सेवा के पदों के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित है, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप महालेखा नियंत्रक के पुनरीक्षित वेतनमान 26000 रु. (नियत) को 1 जनवरी, 1996 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। यह और प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2000

**G.S.R. 880(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Indian Civil Accounts Service (Group "A") Recruitment Rules, 1977, namely:-

1. (i) These rules may be called the Indian Civil Accounts Service (Group "A") Recruitment (Amendment) Rules, 2000.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Civil Accounts Service (Group "A") Recruitment Rules, 1977
  - (a) In rule 3, for clause (vii) of sub-rule (3), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(vii) Controller General of Accounts - Rs. 26000 (Fixed)”;
  - (b) In the SCHEDULE, against serial Number 1, under heading GRADE, for the words, letters and figures, “Controller General of Accounts—Rs. 24050-650-26000”, the following words, letters and figures shall be substituted, namely :—  
“Controller General of Accounts—Rs. 26000 (Fixed).”.

[No. A-12018/2/96/MF.CGA/Gr. A]

V. N. KAILA, Jt. Controller General of Accounts

**Footnote:**—The Principal Rules were published vide Notification number G.S.R. 537, dated 14th April, 1977 and subsequently amended vide:—

- (i) G.S.R 125, dated 27th January, 1989;
- (ii) G.S.R 434(E), dated 24th April, 1992, and
- (iii) G.S.R 12(E), dated 27th December, 1999.

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

Consequent upon implementation of the recommendations of the Fifth Central Pay Commission relating to revision of pay scales of posts in the Organised Group "A" Services, vide Ministry of Finance, Department of Expenditure (Implementation Cell) O. M. No. 6/1/98-IC. 1 dated 30-06-1999 the revised pay scale of Rs. 26000 (Fixed) to the Controller General of Accounts is being given retrospective effect from 1st January, 1996. It is further certified that no one is prejudicially affected by this amendment giving retrospective effect.